ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

4 अप्रैल, 2018 • वर्ष 1, अंक 11

सात दिन – सात पृष्ठ

राजभवन, लखनऊ में पद्मश्री पुरस्कार 2018 एवं वीरता पुरस्कार विजेताओं के अभिनंनदन समारोह के सुअवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

• जे.ई. तथा ए.ई.एस. रोगों के उन्मूलन हेतु 'दस्तक' • स्कूल चलो अभियान की शुरूआत
• कैलाश मानसरोवर व सिंधु यात्रियों को एक लाख रूपये का अनुदान
• गाज़ियाबाद हेतु 1792.19 करोड़ की विकास योजनाएं • निजी स्कूलों की सालाना बढ़ोत्तरी का फार्मूला तय

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

अध्यादेश के प्रमुख बिन्दु

- सत्र 208-19 से ही लागू होगी फीस बढ़ोत्तरी की नई व्यवस्था
- दो वर्गों में बंटेगी फीस - संभावित और वैकल्पिक शुल्क घटक
- तय से अधिक फीस लेने पर पहली बार एक लाख और दूसरी बार पांच लाख जुर्माना
- केवल दाखिले के समय ही स्कूल ले सकेंगे प्रवेश शुल्क, कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं
- साल भर की फीस एक ही बार में नहीं वसूल सकेंगे स्कूल
- बाध्यकारी नहीं होगा किसी भी तरह का वैकल्पिक शुल्क
- स्कूलों से जूते-मोजे और यूनिफार्म खरीदने को बाध्य नहीं होंगे अभिभावक
- पांच वर्ष से पहले स्कूल नहीं बदल सकेंगे विद्यार्थियों की यूनिफार्म
- नए सत्र के लिए फीस जमा कर चुके लोगों के लिए अतिरिक्त फीस वापसी का प्राविधान
- प्री-प्राईमरी स्कूलों पर नहीं लागू होंगे नियम

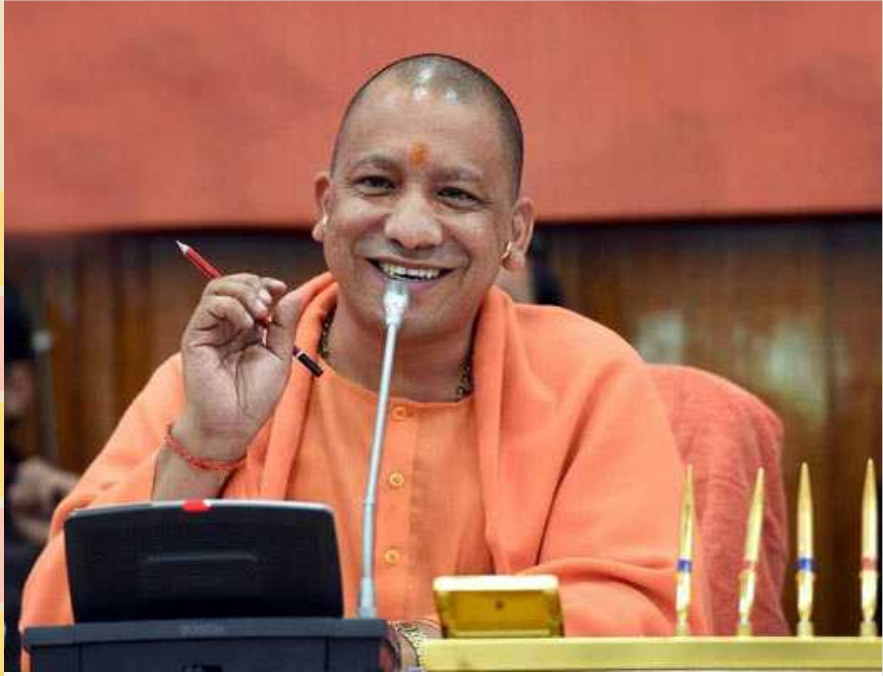

सरकार नहीं चलने देगी निजी स्कूलों की मनमानी

प्रदेश के निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार ने निजी स्कूलों की सलाना बढ़ोत्तरी का फार्मूला निर्धारित कर दिया है। इस फार्मूले के अनुसार निजी स्कूल नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में में गत वर्ष के शुल्क का पांच प्रतिशत जोड़कर प्रतिवर्ष उतनी ही फीस बढ़ा सकेंगे। प्रस्तावित नई व्यवस्था के अनुसार स्कूलों की फीस में अधिकतम सात से आठ प्रतिशत तक की वृद्धि ही की जा सकेगी। प्रस्तावित अध्यादेश उन सभी स्कूलों पर लागू होगा, जिनका वार्षिक शुल्क 20 हजार रूपये से अधिक है।

यह नियम यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तथा अन्य मान्यता प्राप्त/संबद्ध स्कूलों सहित अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त सभी विद्यालयों पर लागू होगा।

निर्धारित फीस से अधिक वसूलने पर होगा जुर्माना

यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए फीस में वृद्धि करता है तो उस पर जुर्माना लगया जायेगा। तय से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों पर पहले वर्ष एक लाख तथा दूसरी बार पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा, जबकि तीसरी बार स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

इसी सत्र से लागू होगी व्यवस्था

फीस वृद्धि का यह फार्मूला इसी शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू होगा। वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मानते हुए इस अध्यादेश के अन्तर्गत स्कूलों को अगले शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से 60 दिन पूर्व आगामी सत्र में प्रस्तावित फीस को अपनी वेबसाइट पर सर्वाजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अध्यादेश के अन्तर्गत स्कूलों को कक्षा 1 से 12 तक के फीस ढांचे का विवरण भी प्रदर्शित करना होगा।

व्यवसायिक गतिविधियों की आय जुड़ेगी स्कूलों के खाते में

प्रत्येक विद्यालय का एक कोष होगा, जिसमें छात्रों की दी गई सुविधाओं और उनसे प्राप्त धनराशि का पूरा विवरण होगा। स्कूल परिसर में आयोजित होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों से प्राप्त होने वाली को स्कूल की आय में शामिल माना जायेगा। इस आय को स्कूल के खाते में जमा किया जायेगा न कि प्रबन्ध समिति अथवा ट्रस्ट के खाते में।

फीस वापसी हेतु भी है व्यवस्था

नई व्यवस्था के अनुसार स्कूल पूरे वर्ष की फीस एक साथ नहीं ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त अधिक जमा की जा चुकी फीस भी स्कूल द्वारा छात्र अथवा अभिभावक को वापस की जायेगी। ■

वर्ष 2017 में टीकाकरण एवं स्वच्छता अभियान के चलते जे.ई./ए.ई.एस. से मृत्यु दर 25 से घटकर 11 प्रतिशत रह गयी थी। इस वर्ष सघन अभियान चलाकर मृत्यु दर जीरो पर लाने का लक्ष्य है।

जे.ई. तथा ए.ई.एस. रोगों के उन्मूलन हेतु 'दस्तक'

जे.ई. तथा ए.ई.एस. रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 'विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा' तथा 'दस्तक' अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की गरीब जनता को हर हाल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं इस प्रकार से उपलब्ध कराई जाएं ताकि रोगों को पनपने से पहले ही दूर किया जा सके। पूर्वांचल में जे.ई. तथा ए.ई.एस. रोगो से विशेषत: बच्चों को खतरा बना रहता है। इन रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोरखपुर में 'विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा' तथा 'दस्तक' अभियान की शुरूआत की। मुख्यमंत्री जी ने पिपराइच के सुभाषनगर में मलिन बस्ती का निरीक्षण किया। उनकी उपस्थिति में पिछले अभियान में छूटे बच्चो को जे.ई. का टीका लगाया गया। बस्ती के कुल 30 बच्चों को टीका लगाया गया।

दस्तक अभियान को जनान्दोलन बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री जी के अनुसार जे.ई./ए.ई.एस. से बचाव के लिए दस्तक अभियान को जनान्दोलन बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के जनप्रतिनिधि इस अभियान से जुड़ें हैं ताकि दिमागी बुखार से लड़ाई में उत्तर प्रदेश को पूरी सफलता मिले।

जे.ई./ए.ई.एस. के विरुद्ध संचालित अभियान में ग्राम प्रधान नेतृत्व करेंगे तथा सभी ग्राम स्तरीय कर्मचारी ए.एन.एम., आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, कोटेदार, लेखपाल, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी घर–घर जाकर लोगों को दिमागी बुखार के प्रति सजग करेंगे तथा लक्षण एवं उपचार की जानकारी देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस अभियान में यूनीसेफ भी जुड़ गया है।

स्वच्छता पर ध्यान देकर होगा ए.ई.एस. से बचाव

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जे.ई. से बचाव के लिए टीका मौजूद है। गोरखपुर जनपद में छूटे हुए 86 हजार बच्चों को 15 दिन में टीका लगा दिया जायेगा। ए.ई.एस. से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है। इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए जनपद के प्रत्येक ग्राम, कस्बे, नगर में स्वच्छता अभियान संचालित किये जायेंगे।

रोग पर नियंत्रण हेतु अस्पतालों में बढ़ी सुविधाएं

इन रोगों के इलाज में मरीजों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए सरकार द्वारा जिला अस्पताल, सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. में बेड, वार्मर एवं वेन्टीलेटर की सुविधाएं बढ़ाई गयी है। रोगियों के इलाज हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की गयी है। केवल गोरखपुर जनपद में ही 30 हजार स्टाफ को संचारी रोगों के प्रति आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 45 विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर योगी जी ने 4727.96 लाख रुपये की 13 निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 869.67 लाख रुपये की 03 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कुल 5597.63 लाख रुपये की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ।

योगी जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराइच के ओ.पी.डी./इमरजेंसी में बने प्रतीक्षालय का उद्घाटन करते हुए वहां की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने अस्पताल के वार्डों का सघन निरीक्षण करते हुए साफ–सफाई एवं दवाओं की उपलब्धता को देखा एवं चिकित्सा प्रणाली को बेहतर से बेहतर बनाने के निर्देश दिये।

9 विभागों के संयुक्त तत्वावधान में दस्तक अभियान संचालित किया जा रहा है। गोरखपुर तथा बस्ती मण्डल के 7 जिलों में 617 जे.ई./ए.ई.एस. गांव में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जायेगा। पीडिएट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पी.आई.सी.यू.) की संख्या 102 से बढ़ाकर 202 की गयी है। दोनों मण्डल के 60 लाख घरों में दस्तक अभियान चलेगा।

स्कूल चलो अभियान से बच्चों को दिखाई शिक्षा की राह

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। शिक्षा की नींव बाल्यकाल से ही मजबूत होनी चाहिए, तभी आगे चलकर शिक्षित नागरिक बनाने तथा समाज की प्रगति में उनके हाथ बंटाने का सपना साकार हो सकता है। इसी सोच के दृष्टिगत बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद गोरखपुर में 'स्कूल चलो अभियान' की शुरूआत की गई।

पहले ही दिन गोरखपुर में हुआ 1000 बच्चों का नामांकन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर प्रसन्न्ता व्यक्त की कि गोरखपुर में 'स्कूल चलो अभियान' के पहले ही दिन 1000 बच्चों का स्कूल में नामांकन हुआ है। सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के निर्देश दिये गये हैं।

नये सत्र से बच्चे पढ़ेगे एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने पर खासा ध्यान दिया गया है। इसलिए नये सत्र से बच्चे एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें पढ़ेंगे, जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं।

बढ़ रही है बेसिक शिक्षा के प्रति रूचि

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सुखद परिणाम है कि बच्चों में बेसिक शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ रही है। वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.36 करोड़ बच्चों का नामांकन हुआ था, जिनकी संख्या वर्ष 2017 में बढ़कर 1.54 करोड़ हो गयी। सभी छात्र–छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को ड्रेस, जूता–मोजा, स्वेटर, बैग और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है।

शिक्षा में गुणवत्ता है प्रदेश सरकार का लक्ष्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बालिकाओं को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' अभियान शुरू किया गया है। जनपद सिद्धार्थनगर पिछड़े जनपद की श्रेणी में आता है। ऐसे में, शिक्षा के स्तर में सुधार सुनिश्चित कर इसे पिछड़े जनपदों की श्रेणी से बाहर लाया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हर हाल में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

बच्चों को मिलेगा अच्छी पढ़ाई का वातावरण

2 से 30 अप्रैल, 2018 के दौरान संचालित किये जा रहे 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा बच्चों को पढ़ाई का अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जायेगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों को इस बात की सम्पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश में चार वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से किसी भी दशा में वंचित न रहने पाये।

रायल्टी फ्री मिट्टी से खनन हुआ आसान

किसानों और आमजन को मिट्टी मिलने में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी को रायल्टी फ्री कर दिया है। अब किसान अपने खेत से मिट्टी खनन कर सकते हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश हैं कि बालू, मौरंग के पट्टे जारी किए जाने की कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करते हुए बालू, मौरंग के खनन का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे स्थानीय लोगों को सस्ते में बालू एवं मौरंग उपलब्ध हो सके और आम नागरिक कम लागत पर अपने पक्के मकान बना सकें।

प्रदेश सरकार ईंट भट्ठा मालिकों से वार्ता करके ईंट का रेट कम करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए ईंट भट्ठों को दी जाने वाली मिट्टी को प्रदेश सरकार रायल्टी फ्री करने पर भी विचार कर रही है। जिलाधिकारी जनपद के ईंट भट्ठा मालिकों से वार्ता करके ईंट का रेट कम कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

देश की सांझी सांस्कृतिक विरासत का भव्य उत्सव

"भारत को एक राष्ट्र बनाने में हर राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों के आदान-प्रदान से देश की एकता को बल मिलता है। इसी भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से लखनऊ में 'ओड़िशा दिवस' का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों प्रदेशों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशों के जुड़ाव को रेखांकित किया गया और पर्यटन की बेहतर संभावनाएं तलाशी गयीं। इस मौके पर एक स्मारिका 'निर्माल्य' व अयोध्या पंचांग का विमोचन किया गया।

हमारी संस्कृति समृद्ध है और विविध भाषाओं के होने के बाद भी भारत में एकता के जो दर्शन होते हैं, वह अद्भुत है। भारतीय संस्कृति लोगों को शान्ति प्रदान करती है। ओड़िशा में जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वहां की रथ यात्रा हम सभी को जोड़ने का काम करती है। विभिन्न समाजों के मेलजोल से विकास को गति मिलती है। उद्योग व व्यापार में भी प्रगति होती है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने ओड़िशा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह उद्गार व्यक्त किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को हम तभी साकार कर सकते हैं, जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमें एक-दूसरे को जानने का अवसर प्राप्त हो। हमारा देश सांस्कृतिक रूप से एक है, जिसकी एक सांझी विरासत है। ओड़िशा राज्य की स्थापना 01 अप्रैल, 1936 को हुई थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की स्थापना आजादी के बाद 24 जनवरी, 1950 को हुई थी। राज्यपाल जी की प्रेरणा से आजादी के बाद इस वर्ष पहली बार यहां अपना यूपी स्थापना दिवस मनाया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत को एक बनाने में हर राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है। ओड़िशा समृद्ध परम्परा के साथ जुड़ा एक महत्वपूर्ण राज्य है। चार धामों में जगन्नाथपुरी यहीं पर स्थित है। यहां जगन्नाथ की रथ यात्रा हम सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री जी ने ओड़िशा समाज हेतु लखनऊ में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए हर सम्भव मदद देने का आश्वासन भी दिया। ■

विभिन्न समाजों के मेलजोल से विकास को गति मिलती है। उद्योग व व्यापार में भी प्रगति होती है।

–राम नाईक
राज्यपाल

लखनऊ में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए हर सम्भव मदद देगी सरकार

–योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

कैलाश मानसरोवर व सिंधु यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है प्रदेश सरकार

कैलाश मानसरोवर एक पावन धार्मिक स्थल है और अधिकांश श्रद्धालु इस पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे देश में स्थित होने के कारण प्रतिवर्ष यहां जाने वाले तीर्थ–यात्रियों की संख्या सीमित होती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफी दुर्गम भी है। इस यात्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर ही वर्तमान सरकार ने इस पावन धाम की यात्रा करने वाले प्रदेश के मूल निवासियों को दिए जाने वाले अनुदान की धनराशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 01 लाख रुपए कर दिया ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा नागरिक सुविधा के साथ इस पवित्र यात्रा को पूरा कर सकें। जो प्रदेशवासी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर या सिंधु दर्शन के लिए जाना चाहेंगे, सरकार उनकी हर सम्भव सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार श्री कैलाश मानसरोवर एवं लद्दाख सिंधु दर्शन के दर्शनार्थियों को अनुदान वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

इस अवसर पर योगी जी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा–2017 के 550 दर्शनार्थियों को 01–01 लाख रुपए के चेक प्रतीक स्वरूप प्रदान किए। उन्होंने 38 सिंधु दर्शन यात्रियों को भी 10–10 हजार रुपए के चेक प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि कैलाश मानसरोवर तथा सिंधु दर्शन यात्रियों को उपलब्ध करायी जा रही राशि उनके बैंक खातों में सीधे पहुंचायी जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू जी के तट पर 'दीपोत्सव' तथा होली पर्व पर ब्रज धाम के बरसाना में 'रंगोत्सव' आयोजित कराया गया। इन कार्यक्रमों की देश और दुनिया में सर्वत्र सराहना की गई। सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम सर्किट, बुद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट विकसित करने का फैसला भी लिया गया है। राज्य सरकार पर्यटन सुविधाओं का विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने में अवश्य सफल होगी।

गाजियाबाद में बन रहा है कैलाश मानसरोवर भवन

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर, सिंधु दर्शन, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले नागरिकों के लिए जहां एक ओर गाजियाबाद में 94 करोड़ रुपए की लागत से कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड के चार धामों की यात्रा पर जाने वाले प्रदेशवासियों के लिए हरिद्वार व बद्रीनाथ में भी उत्तर प्रदेश भवन बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। धार्मिक केन्द्र वास्तव में राष्ट्रीय एकता के केन्द्र हैं। तीर्थ यात्रा से राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है। जब लोग दूसरे राज्यों में तीर्थों के दर्शन को जाते हैं तो भारत माता के प्रति सम्पूर्ण समर्पण की भावना को प्रस्तुत करते हैं।

उत्तर प्रदेश बनेगा धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन

उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न है। यहां पर अयोध्या, मथुरा, गंगा, यमुना, राम सर्किट, बौद्ध सर्किट और कृष्ण सर्किट मौजूद हैं। इन्हें विकसित किया जा रहा है ताकि हर भारतीय खुद को अपनी संस्कृति से जोड़ सके। सरकार, उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए अयोध्या, मथुरा वृन्दावन, गोरखपुर, प्रयाग, नैमिषारण्य, वाराणसी, विन्ध्याचल आदि स्थलों के विकास की वृहद योजना तैयार कर उसे लागू कराया जा रहा है। वर्ष 2019 में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के पावन संगम तट पर आयोजित होने वाले महाकुम्भ के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास युद्धस्तर पर किया जा रहा है। ■

गाज़ियाबाद को मिला 1792.19 करोड़ की विकास योजनाओं का उपहार

उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार गरीबों, किसानों और वंचितों की सरकार है, जो जनकल्याण के लिये तत्पर है। सरकार का मानना है कि जाति, धर्म और समाज को बांटने से विकास नहीं होता। विकास केवल निरन्तर प्रयासों से होता है, जो वर्तमान सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। यह विचार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गाज़ियाबाद में 1792.19 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर व्यक्त किए।

हर घर में बिजली कनेक्शन वाला पहला जनपद बना गाजियाबाद

आजादी के बाद वर्तमान केन्द्र सरकार के आने तक देश में 4 करोड़ परिवार बिजली आपूर्ति से वंचित रह गये थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़ परिवार बिजली आपूर्ति से वंचित थे। वर्तमान सरकार द्वारा हर गरीब के घर में बिजली, गैस, आवास, सुरक्षा, समस्याओं के समाधान की पूर्ति करते हुए राम राज्य की स्थापना की जा रही है। गाजियाबाद प्रदेश का पहला जनपद हो गया है, जिसमें सौभाग्य योजना के अन्तर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक घर में विद्युत कनेक्शन एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने का कार्य तेजी के साथ कर रही है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था हुई बेहतर

कानून–व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार की उपलब्धि यह है कि गत एक वर्ष में कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ। हर व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। इसलिए सरकार अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति तक बिना भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

प्रदेश में 32 लाख गरीबों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन

प्रदेश सरकार द्वारा तेजी के साथ कराये जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 32 लाख गरीब लोगों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिया है। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष जितने विकास कार्य राज्य में किये हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए।

हर बच्चा होगा शिक्षित

सरकारी स्कूलों में शैक्षिक स्तर एवं आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाकर आदर्श विद्यालयों के रूप में बदला जा रहा है। विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को नि:शुल्क यूनीफार्म, पाठ्य पुस्तकें, बस्ते, जूते–मोजे, पौष्टिक एवं ताजा भोजन आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में एक भी बच्चा स्कूल जाने से छूटने न पाये और हर बच्चा शिक्षित व संस्कारित हो। ■

इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण

- यूपी गेट से करहैडा तक 6–लेन एलीवेटेड सड़क
- विद्युत विभाग की सौभाग्य योजना
- जीटी रोड से राजनगर एक्सटेन्शन तक बन्धा रोड का सुदृढ़ीकरण एवं नाले का निर्माण
- मेरठ रोड तिराहे पर रोटरी व ग्रेड सैपरेटर
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आरोग्यम एप
- जीडीए की अनुरक्षित योजनाओं में पारम्परिक के स्थान पर एलईडी लाइट लगाने का कार्य
- बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकास
- अग्निशमन विभाग की 42 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एवं स्मार्ट फायर कन्ट्रोल रूम

शिलान्यास की गई योजनाएं

• प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मधुबन बापूधाम योजना में 856 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य • एकीकृत ऊर्जा विकास योजना • दिल्ली यमनोत्री मार्ग के 18 किमी से खजूरी पुश्ता मार्ग का चौडी़करण एवं सुदृढी़करण का कार्य • अक्षय पात्रा द्वारा मिड–डे मील हेतु केन्द्रीय किचन घर का निर्माण • ग्राम सिरोरा सलेमपुर में हिण्डन नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण • कनावनी गांव की जल निकासी हेतु नाले का निर्माण • मोहन नगर तिराहे से यूपी बॉर्डर तक नाले का निर्माण • हिण्डन एयरफोर्स स्टेशन से आईटीएस टी–प्वाइन्ट तक सड़क का सुधार कार्य • डासना गेट, जवाहर गेट व दिल्ली गेट का रिनोवेशन एवं फसाड लाइटिंग तथा प्राधिकरण एवं कलेक्ट्रेट भवनों के फसाड लाइटिंग का कार्य • राजेन्द्र नगर में लोहिया पार्क के पास आरसीसी नाले का निर्माण • सिटी फॉरेस्ट का जीर्णोद्धार कार्य • नगर पालिका मोदीनगर की ग्राम बेगमाबाद बुदाना में कान्हा गौशाला एवं आवारा पशु आश्रय स्थल का निर्माण

महिलाओं की सुरक्षा व कल्याण हेतु प्रतिबद्ध सरकार

महिलाओं को अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए : मुख्यमंत्री

129 महिलाएं व बच्चे उ.प्र.रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित

पं. धर्मनाथ मिश्र एवं उस्ताद सखावत हुसैन खां को मिला बेगम अख्तर पुरस्कार

महिलाओं को अन्याय और शोषण बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्हें इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गये हैं। महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें अन्याय एवं शोषण से बचाने के लिए हेल्पलाइन '181' प्रारम्भ की गयी है। '1090' पहले से ही संचालित है। प्रदेश सरकार पीएसी की महिला बटालियन के गठन का कार्य कर रही है। साथ ही, महिलाओं में कुपोषण समाप्त करने के लिए 'शबरी संकल्प योजना', बालिकाओं की स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा हेतु अहिल्याबाई योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार एवं बेगम अख़्तर पुरस्कार वितरण समारोह में कुल 129 महिलाओं एवं बच्चों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं 01 लाख रुपए की धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान समय में भी महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपने कार्यों से महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। समाज में व्याप्त संकीर्ण मानसिकता समाप्त करने तथा बालिकाओं को समान अवसर मुहैया कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान संचालित किया। इस अभियान का व्यापक प्रभाव हुआ है। लिंगानुपात में तेजी से सुधार के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही समाज में भी जागरूकता का प्रसार करना आवश्यक है।

महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। विगत वर्ष उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित आगरा की सुश्री नाजिया के सामाजिक कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जागरूक महिलाओं विशेषकर महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर योगदान करना चाहिए। महिला जनप्रतिनिधि ग्राम विकास के कार्यों में रूचि लेकर तथा सामुदायिकता के भाव से विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी द्वारा गांधी जी की ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के संकल्प को पूरा करने में योगदान कर सकती हैं।

> **भारतीय समाज में मातृ शक्ति के प्रति सदैव एक विशिष्ट भाव रहा है। भौतिकता में वृद्धि के कारण भेद प्रारम्भ हुआ, जिसके दुष्परिणाम सामने हैं। भेदभाव के बावजूद बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बालक-बालिका के साथ समान व्यवहार होने पर समाज में सकारात्मक बदलाव आयेगा।**
>
> **–योगी आदित्यनाथ**
> **मुख्यमंत्री**

03 अप्रैल 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

समन्वित कृषि प्रणाली से दोगुनी होगी किसानों की आय

कैबिनेट ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए प्रदेश के नौ एग्राक्लाइमेटिक जोनों के एक–एक जिलों में समन्वित कृषि प्रणाली विकासित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश के कृषि विकास हेतु शोध एवं समन्वित कृषि प्रणाली के प्रयोग से किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत कृषि उपज में वृद्धि होगी, लागत मूल्य में कमी आएगी तथा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। सरकार के इस निर्णय से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु सहायक अभियंता साक्षात्कार 250 के स्थान पर 100 अंक का होगा

विधानमंडल के सत्रावसान को स्वीकृति

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी